आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 28.02.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के लिए 126 करोड़ 83 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया।
- देहरादून में यूकॉस्ट के दो दिवसीय नवाचार महोत्सव का शुभारंभ, 300 से अधिक विद्यार्थी ले रहे हैं हिस्सा।
- लोक निर्माण सचिव ने चारधाम यात्रा से पहले उत्तरकाशी–भटवाड़ी–हर्षिल–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
- मुख्यमंत्री ने लोहाघाट में आईटीबीपी जवानों के साथ और खटीमा में जनसमुदाय संग होली मनाई।

अनुमोदन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के लिए कुल 126 करोड़ 83 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है। इस राशि में मां नन्दा राजजात यात्रा–2026 के अंतर्गत चमोली में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्किंग, बस स्टॉप और मोटर मार्ग निर्माण शामिल है। साथ ही इसमें राष्ट्रीय आयुष मिशन की निर्माणाधीन योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पेयजल व्यवस्था तथा नैनीताल के विद्यालयों की मरम्मत से संबंधित कार्य भी शामिल किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वीकृत धनराशि से संबंधित विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

नवाचार महोत्सव

देहरादून में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद– यूकॉस्ट के आंचलिक विज्ञान केंद्र में दो दिवसीय नवाचार महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आज के समय की आवश्यकता हैं और विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि यह महोत्सव विद्यार्थियों, स्टार्टअप्स और नवाचार से जुड़े लोगों को अपने विचार और तकनीकी उपलब्धियां प्रस्तुत करने का मंच देता है।
कार्यक्रम के दौरान विज्ञान और नवाचार से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं और स्टार्टअप्स ने अपने मॉडल और उत्पाद प्रदर्शित किए। दो पैनल चर्चाएं भी आयोजित की गईं, जिनमें विज्ञान एवं नवाचार में महिलाओं की भूमिका और विज्ञान आधारित स्टार्टअप्स को लेकर चर्चा हुई।
महोत्सव में विद्यार्थियों के लिए रंगोली, नाटक, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर और मॉडल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अन्य विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। बौद्धिक संपदा अधिकार और करियर मार्गदर्शन पर विशेष सत्र रखा गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।

पहल

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सीएससी उत्तराखंड ने "सीएससी ग्रामीण ई–स्टोर" पहल शुरू की है। इस पहल के तहत राज्य के निर्माताओं, वितरकों, एमएसएमई इकाइयों, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को ग्रामीण और अर्ध–शहरी बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए एक संगठित मंच उपलब्ध कराया जा रहा है।
सीएससी नेटवर्क के माध्यम से देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा सहित अन्य पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में उत्पादों की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इससे उत्पादकों को एक व्यवस्थित और पारदर्शी वितरण प्रणाली मिलेगी।
इस पहल के अंतर्गत डेयरी, कृषि और ऑर्गेनिक उत्पादों के साथ स्थानीय ब्रांड्स और स्वयं सहायता समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों द्वारा तैयार उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे महिला समूहों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध होगा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर

हरिद्वार ज़िले के, जे एन सिन्हा मेमोरियल उप जिला चिकित्सालय रुड़की में 9 बेड का आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर तैयार किया गया है। यह ट्रॉमा सेंटर सीएसआर मद के माध्यम से लगभग 20 लाख रुपये की लागत से विकसित किया गया है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा पूर्व में चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान आपातकालीन सेवाओं में कमी पाई गई थी, जिसके बाद ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की पहल की गई। अब इस ट्रॉमा सेंटर में आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल और बीमार मरीजों को यहां त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कल ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर शुरू होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिल रही है। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय प्रशासन को मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए।

विकास कार्यक्रम समीक्षा

देहरादून स्थित सिविल सेवा संस्थान में ग्राम्य विकास सचिव धीराज गर्ब्याल की अध्यक्षता में सभी ज़िलों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ज़िले में पलायन रोकने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जाए। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने श्रम, कौशल विकास और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने को कहा।

उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से समूहों को तकनीकी सहयोग देने और कृषि आधारित उत्पादों के विपणन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने और स्वरोजगार के लिए अधिक से अधिक इच्छुक युवाओं को चिह्नित करने के निर्देश भी दिए गए।

स्थलीय निरीक्षण

लोक निर्माण सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तरकाशी–भटवाड़ी–हर्षिल–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

सचिव ने बीआरओ अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस वर्ष 15 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–34 को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। उन्होंने यात्रा मार्ग से मलबा हटाने, डेंजर और लैंडस्लाइड जोन में आवश्यक कटिंग कर चौड़ाई बढ़ाने तथा हॉट मिक्स का कार्य कराने के निर्देश दिए। स्वाड़ी–गाड़ में निर्माणाधीन 85 मीटर स्पान स्टील सेतु के कार्य में तेजी लाने को कहा गया। यात्रा शुरू होने से पहले स्टील गर्डर सेतु की लॉन्चिंग, डेक स्लैब और एप्रोच रोड का निर्माण पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

मुखवा से धराली तक पैदल मार्ग और पैदल सेतु का भी निरीक्षण किया गया। धराली क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पैदल सेतु और धराली से हर्षिल के बीच दो स्थानों पर क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण कार्य शुरू न होने पर सचिव डॉ० पांडेय ने असंतोष जताया और तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

होली उत्सव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के अवसर पर चंपावत ज़िले के लोहाघाट स्थित 36वीं वाहिनी आईटीबीपी पहुंचकर देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के साथ उत्सव मनाया। उन्होंने जवानों को होली की शुभकामनाएं दीं और उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों की कठिन परिस्थितियों में तैनात हिमवीरों का योगदान अतुलनीय है और उनका त्याग व समर्पण पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री, उधमसिंह नगर क खटीमा के सनातन धर्मशाला रामलीला मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में भी शामिल हुए। यहां उन्होंने पारंपरिक कुमाऊँनी, शास्त्रीय और थारू होली गायन में सहभागिता कर जनसमुदाय के साथ उत्सव की खुशियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि होली हमारी लोक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जो प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देती है।

समीक्षा

देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंथन सभागार में रोड कटिंग कार्यों की समीक्षा और नई अनुमति के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया गया कि अप्रैल माह तक सभी संचालित निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं।

प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि रोड कटिंग की अनुमति सशर्त दी जाए और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। मानकों के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर भारी अर्थदंड लगाने को कहा गया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अनुमति देते समय एजेंसियों से शपथ पत्र लिया जाए कि वे तय समय में कार्य पूरा करेंगी। निर्माण स्थलों की देखरेख के लिए जूनियर अभियंता की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

श्री उनियाल ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय और समेकित योजना के तहत कार्य करें, ताकि बार–बार सड़कों को न खोदना पड़े। निर्माण कार्य के बाद सड़कों को निर्धारित मानकों के अनुसार ठीक करने को कहा गया।

मानक मंथन

देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो, बीआईएस की देहरादून शाखा द्वारा "मानक मंथन" कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय साहसिक पर्यटन सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से जुड़ा आईएस 21101:2014 मानक रहा। इसमें साहसिक पर्यटन ऑपरेटर, प्रमाणन निकाय, परीक्षण एवं निरीक्षण एजेंसियां, नियामक संस्थाएं और उपभोक्ता प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर पर्यटन विभाग के अपर सचिव अभिषेक रुहेला ने कहा कि उत्तराखंड को सुरक्षित और जिम्मेदार एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए स्पष्ट मानकों और जोखिम प्रबंधन का सख्ती से पालन जरूरी है। बीआईएस देहरादून के निदेशक एवं प्रमुख सौरभ तिवारी ने बताया कि आईएस 21101:2014 साहसिक गतिविधियों में जोखिम आधारित प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने का आधार प्रदान करता है, जो पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

तकनीकी सत्र में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, गोवा के प्रतिनिधि ने मानक के प्रमुख प्रावधानों पर जानकारी दी। इसमें सुरक्षा नीति, जोखिम पहचान, संचालन नियंत्रण, उपकरणों के रखरखाव, आपातकालीन तैयारी, प्रशिक्षित गाइड, प्रशिक्षण, घटना रिपोर्टिंग और सतत सुधार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई।